

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4863
उत्तर देने की तारीख: 01.04.2025

मैट्रिक-पूर्व अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता

4863. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मैट्रिक-पूर्व अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रचार के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और क्या वर्ष 2019-22 के बीच समाचारपत्रों अथवा अन्य मीडिया में विज्ञापन देने पर कोई व्यय नहीं किया गया;
- (ख) यदि हां, तो विद्यालय स्तर पर चलाए गए अभियानों सहित ऐसे प्रचार प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पात्र छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक कदमों की योजना बनाई जा रही है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2019-2022 के बीच समाचार पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से आउटरीच को प्रोत्साहन देने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

- i. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों को हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है।
- ii. रेडियो-कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है।
- iii. योजना के ब्यौरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किये जाते हैं।

उपरोक्त योजना के तहत वर्ष 2019-2022 के बीच व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

	रशि (रु. में)
रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से	36,86,415
समाचार पत्रों में विज्ञापन	39,94,848
कुल	76,81,263

(ग): उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
